::आयुक्त (अपील्स) का कार्यालय,वस्तु एवं सेवा करऔर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क::
O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), GST & CENTRAL EXCISE,
द्वितीय तल,जी एस टी भवन / 2nd Floor, GST Bhavan,
रेस कोर्स रिंग रोड, / Race Course Ring Road,
राजकोट / Rajkot – 360 001
Tele Fax No. 0281 – 2477952/2441142Email: commrappl3-cexamd@nic.in

सत्यमेव जयते

रजिस्टर्डडाकए.डी. द्वारा :- DIN- 20230364SX000000B495

क	अपील / फाइलसंख्या/ Appeal /File No.	मूलआदेशसं / OIO No.	दिनांक/ Date
	GAPPL/COM/STP/1878/2022	10/AC/JAM-II/2022-23	17-05-2022

ख अपील आदेश संख्या(Order-In-Appeal No.):

RAJ-EXCUS-000-APP-058-2023

आदेश का दिनांक / Date of Order:	07.03.2023	जारी करने की तारीख / Date of issue:	09.03.2023

श्री शिव प्रताप सिंह, आयुक्त (अपील्स), राजकोट द्वारा पारित /
Passed by Shri Shiv Pratap Singh, Commissioner (Appeals), Rajkot.

ग अपर आयुक्त/ संयुक्त आयुक्त/ उपायुक्त/ सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर/वस्तु एवंसेवाकर, राजकोट / जामनगर / गांधीधाम। द्वारा उपरलिखित जारी मूल आदेश से सृजित: /
Arising out of above mentioned OIO issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioner, Central Excise/ST / GST, Rajkot / Jamnagar / Gandhidham :

घ **अपीलकर्ता**&प्रतिवादी का नाम एवं पता /Name & Address of the **Appellant** & Respondent :-

M/s. Shri Sahdevsinh Pabubha Manek, Near Vyomani Mata Temple, Okha Port, Dist. Devbhoomi Dwarka.

इस आदेश(अपील) से व्यथित कोई व्यक्ति निम्नलिखित तरीके में उपयुक्त प्राधिकारी / प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है।/
Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way.

(A) सीमा शुल्क ,केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील,केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम ,1944 की धारा 35B के अंतर्गत एवं वित्त अधिनियम, **1994** की धारा **86** के अंतर्गत निम्नलिखि+त जगह की जा सकती है ।/

Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section 35B of CEA, 1944 / Under Section 86 of the Finance Act, 1994 an appeal lies to:-

(i) वर्गीकरण मूल्यांकन से सम्बन्धित सभी मामले सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठ, वेस्ट ब्लॉक नं 2, आर॰ के॰ पुरम, नई दिल्ली, को की जानी चाहिए ।/

The special bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No. 2, R.K. Puram, New Delhi in all matters relating to classification and valuation.

(ii) उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में बताए गए अपीलों के अलावा शेष सभी अपीलें सीमा शुल्क,केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट)की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका,,द्वितीय तल, बहुमाली भवन असावा अहमदाबाद- ३८००१६को की जानी चाहिए ।/

To the West regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at, 2nd Floor, Bhaumali Bhawan, Asarwa Ahmedabad-380016in case of appeals other than as mentioned in para- 1(a) above

(iii) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील)नियमावली, 2001, के नियम 6 के अंतर्गत निर्धारित किए गये प्रपत्र EA-3 को चार प्रतियों में दर्ज किया जाना चाहिए । इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की माँग ,ब्याज की माँग और लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम,5 लाख रुपए या **50** लाख रुपए तक अथवा **50** लाख रुपए से अधिक है तो क्रमश: **1,000/-** रुपये, **5,000/-** रुपये अथवा **10**,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्टार के नाम से किसी भी सार्वजिनक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए । संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है । स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ **500/-** रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा ।/

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 / as prescribed under Rule 6 of Central Excise (Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against one which at least should be accompanied by a fee of Rs. 1,000/- Rs.5000/-, Rs.10,000/- where amount of duty demand/interest/penalty/refund is upto 5 Lac., 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asst. Registrar of branch of any nominated public sector bank of the place where the bench of any nominated public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated. Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs. 500/-.

(B) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील, वित्त अधिनियम,1994की धारा **86(1)** के अंतर्गत सेवाकर नियमवाली, **1994**, के नियम **9(1)** के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-5में चार प्रतियों में की जा सकेगी एवं उसके साथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो, उसकी प्रति साथ में संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां सेवाकर की माँग ,ब्याज की माँग और लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम,5 लाख रुपए या **50** लाख रुपए तक अथवा **50** लाख रुपए से अधिक है तो क्रमश: **1,000/-** रुपये, **5,000/-** रुपये अथवा **10**,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्टार के नाम से किसी भी सार्वजिनक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए । संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है । स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ **500/-** रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा ।/

Appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act, 1994, to the Appellate Tribunal Shall be filed in triplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and Shall be accompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fees of Rs. 1000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied of Rs. 5 Lakhs or less, Rs.5000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than five lakhs but not exceeding Rs. Fifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the Assistant Registrar of the bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is situated. // Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs.500/-.

(i) वित्त अधिनियम,1994की धारा **86** की उप-धाराओं **(2)** एवं **(2A)** के अंतर्गत दर्ज की गयीं अपील, सेवाकर नियमवाली, **1994**, के नियम **9(2)** एवं **9(2A)** के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-7 में की जा सकेगी एवं उसके साथ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधवा आयुक्त **(अपील)**, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा पारित आदेश की प्रतियाँ संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और आयुक्त द्वारा सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर, को अपीलीय न्यायाधिकरण को आवेदन दर्ज करने का निर्देश देने वाले आदेश की प्रति भी साथ में संलग्न करनी होगी । /

The appeal under sub section (2) and (2A) of the section 86 the Finance Act 1994, shall be filed in For ST.7 as prescribed under Rule 9 (2) &9(2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissioner authorizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise/ Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal.

(ii) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सेस्टेट) के प्रति अपीलों के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम **1944** की धारा **35**एफ के अंतर्गत, जो की वित्तीय अधिनियम, **1994** की धारा **83** के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, इस आदेश के प्रति अपीलीय प्राधिकरण में अपील करते समय उत्पाद शुल्क/सेवा कर मांग के **10** प्रतिशत **(10%)**, जब मांग एवं जुर्माना विवादित है, या जुर्माना, जब केवल जुर्माना विवादित है, का भुगतान किया जाए, बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत जमा कि जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रुपए से अधिक न हो।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत "मांग किए गए शुल्क" मे निम्न शामिल है

(i) धारा **11** डी के अंतर्गत रकम
(ii) सेनवेट जमा की ली गई गलत राशि
(iii) सेनवेट जमा नियमावली के नियम **6** के अंतर्गत देय रकम

- बशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान वित्तीय (सं॰ **2**) अधिनियम **2014** के आरंभ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन स्थगन अर्ज़ी एवं अपील को लागू नहीं होगे।/

For an appeal to be filed before the CESTAT, under Section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under Section 83 of the Finance Act, 1994, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute, provided the amount of pre-deposit payable would be subject to a ceiling of Rs. 10 Crores,

Under Central Excise and Service Tax, "Duty Demanded" shall include :
(i) amount determined under Section 11 D;
(ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
(iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules

- provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.

(C) **भारत सरकार कोपुनरीक्षण आवेदनं :**
Revision application to Government of India:

इस आदेश की पुनरीक्षणयाचिका निम्नलिखित मामलो में,केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम,1994 की धारा **35**EE के प्रथमपरंतुक के अंतर्गतअवर सचिव, भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन ईकाई,वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, को किया जाना चाहिए। /

A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35B ibid:

(i) यदि माल के किसी नुकसान के मामले में, जहां नुकसान किसी माल को किसी कारखाने से भंडार गृह के पारगमन के दौरान या किसी अन्य कारखाने या फिर किसी एक भंडार गृह से दूसरे भंडार गृह पारगमन के दौरान, या किसी भंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रसस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में माल के नुकसान के मामले में।/

In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse

(ii) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात कर रहे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर भरी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के छुट (रिबेट) के मामले में, जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात की गयी है। /

In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.

(iii) यदि उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर, नेपाल या भूटान को माल निर्यात किया गया है। /

In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.

(iv) सुनिश्चित उत्पाद के उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो ड्यूटी क्रेडीट इस अधिनियम एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत मान्य की गईं है और ऐसे आदेश जो आयुक्त (अपील) के द्वारा वित्त अधिनियम (नं॰ **2**),1998 की धारा **109** के द्वारा नियत की गई तारीख अथवा समायाविधि पर या बाद में पारित किए गए है।/

Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

(v) उपरोक्त आवेदन की दो प्रतियां प्रपत्र संख्या EA-8 में, जो की केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील)नियमावली,2001, के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, इस आदेश के संप्रेषण के **3** माह के अंतर्गत की जानी चाहिए । उपरोक्त आवेदन के साथ मूल आदेश व अपील आदेश की दो प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए। साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, **1944** की धारा **35**-EE के तहत निर्धारित शुल्क की अदायगी के साक्ष्य के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। /

The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

(vi) पुनरीक्षण आवेदन के साथ निम्नलिखित निर्धारित शुल्क की अद्दायगी की जानी चाहिए।
जहां संलग्न रकम एक लाख रूपये या उससे कम हो तो रूपये 200/- का भुगतान किया जाए और यदि संलग्न रकम एक लाख रूपये से ज्यादा हो तो रूपये 1000 -/ का भुगतान किया जाए।

The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved in Rupees One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

(D) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशो का समावेश है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए शुल्क का भुगतान, उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिये। इस तथ्य के होते हुए भी की लिखा पढ़ी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय नयाधिकरण को एक अपील या केंद्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है । / In case,if the order covers variousnumbers of order- in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each.

(E) यथासंशोधित न्यायालय शुल्क अधिनियम, **1975**, के अनुसूची-I के अनुसार मूल आदेश एवं स्थगन आदेश की प्रति पर निर्धारित **6.50** रुपये का न्यायालय शुल्क टिकिट लगा होना चाहिए। /

One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act,1975, as amended.

(F) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्य विधि) नियमावली, **1982** में वर्णित एवं अन्य संबन्धित मामलों को सम्मिलित करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। /

Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

(G) उच्च अपीलीय प्राधिकारी को अपील दाखिल करने से संबंधित व्यापक, विस्तृत और नवीनतम प्रावधानों के लिए, अपीलार्थी विभागीय वेबसाइट www.cbec.gov.in को देख सकते है । /

For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website www.cbec.gov.in

अपील आदेश /ORDER-IN-APPEAL

Shri Sahdevsinh Pabubha Manek, Near Vyomani Mata Temple, Okha Port-361 350 (hereinafter referred to as "appellant") filed appeal No. GAPPL/COM/STP/1878/2022 against the Order-In-Original No. 10/AC/JAM-II/2022-23 dated 17.05.2022 (hereinafter referred to as 'impugned order') passed by the Assistant Commissioner, Central GST Division- II, Jamnagar (hereinafter referred to as "the adjudicating authority").

2. Facts of the case, in brief, are that a show cause notice dated 18.10.2021 was issued to the appellant demanding service tax of Rs.19,04,685/- on the ground of difference between value of services as per ST-3 returns and ITR. The adjudicating authority, by the impugned order, confirmed the demand of Rs.8,06,114/- along with interest under Section 75 of the Finance Act 1994 and imposed penalty of Rs.8,06,114/- under Section 78 of the Finance Act 1994. He also imposed penalties of Rs.10,000/- under Section 77(2) of the Finance Act, 1994.

3. Being aggrieved, the appellants filed present appeals wherein the appellant contended that;

- They had paid service tax liability of Rs.18,22,953/- on 'cargo handling services', for the quarter January 2017 to March 2017 along with appropriate interest on 30.05.2017 and hence the issue of notice dated 18.10.2021 was against the provisions of Section 73(3) of Finance Act, 1994.
- With respect of GTA service, they had no liability to pay service tax since the said service was under 'reverse charge mechanism'. Thus, they had no pending service tax liability as on 18.10.2021 and hence their case is covered within the provisions of Section 73(3) of the Finance Act, 1994.
- The action of the adjudicating authority to disallow Cenvat credit is untenable in law being beyond the scope of show cause notice.
- GTA service is covered under Sr.No.2 of Notification No.30/2012-ST, according to which the service recipient is liable to pay service tax. Therefore, demanding service tax from the service provider is untenable in law.
- The impugned order, disallowing Cenvat credit of Rs.7,24,382/-, is untenable in law being against the provisions of Cenvat Credit Rules, 2004. The findings of the adjudicating authority that relevant Cenvat invoices were not provided by the appellant and the appellant was not entitled to avail Cenvat credit after one year from the date of issue of invoices are self-contradictory because without possession of relevant invoices he could not have ascertained that these invoices were more than one year old. None of the invoices is more than one year old so as to disallow Cenvat credit.
- They have availed Cenvat credit of 'input services' namely 'barge rental services', 'manpower supply services', 'CA services' etc which were used in

providing their output services and hence, they are eligible to avail Cenvat credit.

- The finding of the adjudicating authority that they have contravened the provisions of rule 9(1) and 9(2) of Cenvat Credit Rules, 2004 are nothing but imagination since the appellant have enclosed copies of relevant invoices. The finding of the adjudicating authority regarding contravention of rule 9(9) of the Cenvat Credit Rules, 2004 (non-reflection of relevant Cenvat details in ST-3 return) is procedural lapse and Cenvat credit cannot be disallowed. They relied upon case of *AD Vision-2011 (21) STR.455 (Tri-Ahmd).*
- The impugned order is unsustainable in law being barred by limitation as necessary ingredients to invoke proviso to Section 73(1) of the Finance Act, 1994 like fraud or collusion or wilful mis-statement or suppression of facts or contravention of any provisions of the Act with intent to evade payment of service tax are absent in the present case.
- The impugned order, confirming recovery of interest and imposing penalty is unsustainable in law.

4.1 Shri Dinesh Jain, Chartered Accountant appeared for personal hearing on 15.02.2023. He reiterations the submissions in the appeal. He submitted that the appellant inadvertently did not include the value of taxable services rendered during the period January-March 2017, in their ST-3 return although they made full payment of tax and interest subsequently through challan/debiting of Cenvat credit. The adjudicating authority has accepted the payments made through challans but has not accepted the payments made by debiting of CENVAT credit on the ground of it not being reflected in ST-3 return. The appellants have enclosed the invoices with the appeals and relied upon CESTAT order in case of AD Vision Vs CCE Ahmedabad, Apartment from above, a small part of demand is in respect of GTA services. The appellant submitted that the liability in case of GTA services is on the recipients on RCM basis. He undertook to make additional submissions within a week to support that the recipients were eligible for RCM. He requested to drop the demand and set aside the Order-in-Original allowing the appeal.

4.2 The appellant, vide letter dated 20.02.2023 submitted that they had provided transportation services amounting to Rs.5,44,880/- to M/s Bharat Petroleum Corporation Ltd, which is 'body corporate' who is liable to pay service tax under RCM.

5. I have carefully gone through the facts of the case, the impugned order, the appeal memoranda and written as well as oral submissions made by the Appellants. The issue to be decided is whether the impugned order, in the facts of this case, confirming demand on Appellant and imposing penalty is correct, legal and proper or not.

In this regard, I find that, the show cause notice was issued on the ground

of difference between value of services as per ST-3 returns and ITR. The appellant submitted before the adjudicating authority that they had paid service tax of Rs.18,22,953/- on 'cargo handling services', for the quarter January 2017 to March 2017 along with appropriate interest on 30.05.2017. As per the facts of the case, the appellant had paid Rs.10,98,571/- through challan and Rs.7,24,382/- by utilizing Cenvat credit. The adjudicating authority, while considering the payment made by the appellant, observed that relevant Cenvat invoices were not provided by the appellant and the appellant was not entitled to avail Cenvat credit after one year from the date of issue of invoices. The appellant, contended that the observation of the appellant is self-contradictory because without possession of relevant invoices he could not have ascertained that these invoices were more than one year old. From the copies of the invoices produced by the appellant, under which Cenvat credit was taken, I find that the invoices pertains to the period January 2017 to March 2017 and the appellant had paid the tax on 30.05.2017. Thus, it is evident that the invoices are not more than one year old and therefore, the Cenvat credit availed by the appellant is in order.

7. I also observe that the adjudicating authority has not given any finding with regard to the claim of the appellant that the liability to pay service tax on GTA service is on the recipient of the service. As per the invoices produced by the appellant, the appellant had provided GTA service to body corporate and partnership firms. Therefore, I hold that the demand of service tax is not sustainable on the value of such services provided as the service recipient is liable to pay service tax as per Sr.No.2 of Notification No.30/2012-ST.

8. In view of above, I set aside the demand and allow the appeal.

९. अपीलकर्ताओ द्वारा दर्ज की गई अपीलो का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है ।

9. The appeal filed by the Appellant is disposed off as above.

सत्यापित / Attested

Superintendent
Central GST (Appeals)
Rajkot

7-3-2023

(शिव प्रताप सिंह/ SHIV PRATAP SINGH)
आयुक्त (अपील)/Commissioner (Appeals)

By R.P.A.D.

सेवा में श्री सहदेवसिंह पबुभा मानेक व्योमनी माता मंदिर के पास ओखा पोर्ट – 361 350	To Shri Sahdevsinh Pabubha Manek, Near Vyomani Mata Temple, Okha Port-361 350

प्रतिलिपि :-

1) मुख्य आयुक्त,वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गुजरात क्षेत्र,अहमदाबाद ।
2) प्रधान आयुक्त,वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, राजकोट आयुक्तालय, राजकोट ।
3) सहायक आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मण्डल जामनगर-II
4) गार्ड फाइल।